भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1560
जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2014 को दिया जाना है

पुरानी मिलों का पुनरुत्थान

1560. श्री फिरोज़ वरूण गांधी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में उन मिलों के पुनरुत्थान और पुनर्स्थापना के लिए कोई कदम उठा रही है जो पांच वर्ष से भी अधिक समय से कार्य नहीं कर रहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि कितनी है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क और ख): चूंकि उद्योग राज्य का विषय है, इसलिए पुरानी मिलों का पुनरुद्धार राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार या संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, जिनके तहत ये मिलें सार्वजनिक क्षेत्र में आती हैं, का विशेषाधिकार है। भारी उद्योग विभाग का सरोकार अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से है। इसमें उनके पुनरुद्धार/समापन पर निर्णय भी शामिल है। सरकार ने भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के पेपर मिल वाले दो उद्यमों नेपा लिमिटेड और नगालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी) के लिए पुनरुद्धार पैकेज का अनुमोदन क्रमश: सितम्बर, 2012 और जून, 2013 में कर दिया है। पुनरुद्धार योजना के अनुमोदन के बाद, सरकार ने अब तक नेपा लिमिटेड और एनपीपीसी लिमिटेड को उनके पुनरुद्धार के लिए क्रमश: ₹85.28 करोड़ और ₹100 करोड़ जारी कर दिए हैं।

*****